IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"ईरान–इज़राइल संघर्ष और भारतः एक अध्ययन"

[1] आशिक हुसैन खान

पी–एच.डी. रिसर्च स्कॉलर (राजनीति विज्ञान)

स्कूल ऑफ सोशल साईंसेस, दे.अ.वि.वि. इन्दौर, (म.प्र.)।

[2] डॉ. संजू गांधी

प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान),

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ, (म.प्र.)।

- **शोध सारांश :**

ईरान–इज़राइल संघर्ष उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दोनों देशों के धार्मिक और वैचारिक विभाजन, इज़राइल विरोधी समूहों को ईरान द्वारा दिए जाने वाला समर्थन, भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के कारण हमेशा बना रहता है। भारत की चुनौती भविष्य की तैयारी करते हुए वर्तमान संकट का प्रबंधन करना है। भारत को अफ्रीका और रूस जैसे देशों से अधिक ऊर्जा खरीदकर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। साथ ही, उसे जुड़े रहने के लिए चाबहार बन्दरगाह और अन्य व्यापार मार्गों के विकास में तेजी लाना चाहिए। भारत को ईरान और इज़राइल दोनों के साथ राजनयिक संबंध भी खुले रखना चाहिए। अपने हितों की रक्षा के लिए तटस्थता के साथ तैयार रहना भी आवश्यक हैं।

- **शब्द संकेत :** ईरान–इज़राइल, तटस्थता, भू–राजनीतिक, परमाणु अप्रसार, क्षेत्रीय सहयोग, छाया युद्ध, वैश्विक सुरक्षा।

➢ ईरान–इज़राइल संघर्ष पृष्ठभूमि :

1979 तक ईरान और इज़राईल के संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे। उस समय तक ईरान में पहलवी राजतंत्र स्थापित था और मध्य–पूर्व में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी माना जाता था। 1979 में आयातुल्लाह ख़ुमैनी की क्रांति ने शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। ख़ुमैनी ने स्वयं को विश्व के 'पीड़ितों का रक्षक' बताया और अमेरिका तथा इज़राइल के साम्राज्यवाद को खारिज करना अपनी वैचारिक बुनियाद बताया। हालांकि, ईरान ने फ़लस्तीन के विभाजन की उस योजना का विरोध

किया था, जिसकी वजह से 1948 में इज़राईल राज्य का गठन हुआ था। ख़ुमैनी की सरकार ने इजराईल से सारे संबंध तोड़ लिए। इज़राइली नागरिकों के पासपोर्ट को वैद्यता प्रदान करना बंद कर दिया और तेहरान स्थित इज़रायली दूतावास को जब्त कर उसे फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाईजशन (पीएलओ) को सौंप दिया। ईरान ने लगातार फलस्तीन मुद्दे को उठाया और खुद को इस्लामी ताकत के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। 1990 के दशक तक इज़राइल में ईरान के लिए दुश्मनी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि उस दौर में इज़राइल के लिए सबसे बडा दुश्मन सद्दाम हुसैन का ईराक़ था। एक गुप्त कार्यक्रम के ज़रिए अमेरिका ने 1980 से 1988 के बीच ईरान को पड़ोसी इराक़ के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए हथियार दिए थे। लेकिन इज़राइल ने समय के साथ ईरान को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़े ख़तरे के रूप में देखना शुरू कर दिया था।

ईरान को एक और बड़ी क्षेत्रीय शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। ईरान मुख्य रूप से फ़ारसी और शिया बहुल देश है, जबकि अरब जगत ज्यादातर सुन्नी आबादी वाला है। ईरान की सरकार को यह एहसास हुआ कि उसके विरोधी देश किसी भी दिन उस पर हमला कर सकते हैं। इसी आशंका की वजह से उसने एक रणनीतिक योजना पर काम शुरू किया। ईरान से गठबंधन करने वाले संगठनों का एक नेटवर्क तैयार हुआ। इन संगठनों ने अपने–अपने हितों के अुनसार सशस्त्र कार्रवाई को अंजाम दिया। आज ईरान का तथाकथित 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक फैला हुआ है।

इज़राइल चुप नहीं बैठा, उसने ईरान और उसके सहयोगी गुटों पर हमले किए। ये हमले अक्सर तीसरे दशों में हुए, जहां ईरान अपने समर्थक सशस्त्र संगठनों को धन और संसाधन मुहैया कराता हैं। ईरान और इज़राइल के बीच इस टकराव को 'छाया युद्ध' कहा गया है, क्योंकि दोनों देशों ने अधिकतर मौकों पर अपनी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि किए बिना एक–दूसरे को निशाना बनाया। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना और उसे परमाणु हथियार संपन्न बनने से रोकना, इज़राइल का प्रमुख लक्ष्य है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के प्रमुखों और अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों पर हुए हमलों के लिए इज़राइली खुफिया एजेंसी को ज़िम्मेदार ठहराया है। फिलहाल, दोनों देश एक–दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं।

➢ ईरान– इज़राइल युद्ध का वर्तमान स्वरूप :

ईरान–इज़राइल युद्ध 13 जून 2025 से 24 जून 2025 तक चलने वाला बारह दिवसीय युद्ध था, जो मध्य–पूर्व में 2025 में लड़ा गया एक सशस्त्र युद्ध था। इसकी शुरूआत ईरान में प्रमुख सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर इज़राइल द्वारा अचानक हमलें करने से शुरू हुई। 1 अप्रैल को इजराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर बमबारी की, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। इस हमले के जवाब में ईरान और उसके प्रतिनिधियों ने 13 अप्रैल को इज़राइल के अंदर हमले शुरू किए। जिसके बाद ईरान ने इज़राइल पर अधिक आलोचनात्मक रूख अपनाया तब से युद्ध की स्थिति बनना शुरू होती गई। इसका सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा। इज़राइल को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता हैं, जो उसके लिए अस्तित्व का ख़तरा बन जाएगा। 13 जून 2025 से तीव्र सैन्य टकराव का होना शुरू हुआ। पहले इज़राइल ने हमला किया फिर ईरान ने जवाबी मिसाइलों की बरसात की। उसके बाद से दोनों देशों के

बीच रिश्तों में गहरा तनाव का वातावरण निर्मित हो गया। इज़राइल ने ईरान पर ''ऑपरेशन राइजिंग लायन'' के तहत एयर स्ट्राइक कर तेहरान, मिडिल ईरान के परमाणु व सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जिसमें कई टॉप सैन्य और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने ''ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3'' के तहत ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव, हाइफा, यरूशलम और बेयर शेवा जैसे कई शहरों में दागी, इसकी वजह से सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में शरण लिए और बडी संख्या में नागरिक घायल हुए।

➢ ईरान– इज़राइल युद्ध एवं भारत का पक्ष :

थिंक टैंक ओआरएफ में स्ट्रैटिज़िक स्टडीज के फेलो कबीर तनेजा कहते हैं, ''इज़राइल और ईरान के बीच टकराव में भारत का रूख़ संतुलनवादी होगा। बाकी दुनिया की तरह भारत परमाणु शक्ति संपन्न ईरान के पक्ष में नहीं हैं।'' इंडो–पैसिफिक एनसिस्ट डेरेक ग्रॉसमैन मानते हैं कि, ''भारत इज़राइल का समर्थन करेगा लेकिन ये बिना शर्त नहीं होगा। निश्चित तौर पर भारत ईरान पर इज़राइली हमले का समर्थन नहीं करेगा।'' भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों को डिप्लोमैसी के ज़रिए विवाद को सुलझाना चाहिए और टकराव से बचना चाहिए। भारत ने कहा, ''ईरान और इज़राइल दोनों से भारत के दोस्ताना संबंध है और हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं।'' दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वेस्ट एशिया स्टडी सेंटर में प्रोफेसर रहे आफताब कमाल पाशा का मानना है कि ईरान– इज़राइल जंग सिर्फ दोनों देशों के बीच सीमित नहीं हैं बल्कि इस जंग में अमेरिका का हाथ है, क्योंकि जो ड्रोन ईरान ने इज़राइल पर हमले के लिए भेजे थे, उन्हें अमेरिका ने मारकर गिराए और उन्हें इज़राइल तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसके अलावा सऊदी अरब और जॉर्डन ने भी अमेरिकी दबाव में इज़राइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया। उन्होनें कहा कि–''सऊदी, कतर, बहरीन और यूएई तो अमेरिका के पिछलग्गू हैं। जो अमेरिका कहेगा, ये करेंगे।'' हालांकि, ईरान और इज़राइल को लेकर भारत किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में नहीं हैं। इजराइल एकमात्र देश था जिसने 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारत का समर्थन किया था। इसलिए भारत इज़राइल का समर्थन करेगा वहीं दूसरी ओर ईरान से भारत ने सभी पुराने संबंध सीमित कर लिए है। ना तेल खरीद रहे हैं और ना गैस। चाबहार का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हैं। अतः हमारा रूख भी तटस्थता के साथ ही अमेरिका के निर्णय की ओर भी रहेगा।

➢ ईरान–इजराइल युद्ध का भारत पर असर :

ईरान–इज़राइल युद्ध से भारत की ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं। इस युद्ध से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में बाधा उत्पन्न होने, भारतीय प्रवासियों के प्रभावित होने, सामरिक संपर्क में व्यवधान उत्पन्न होने, भारत के लिए कूटनीतिक तंगी उत्पन्न होने की पूरी संभावना होती है। तेल महंगा होगा तो भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार पर सीधा असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था की गति धीमी होगी। भारत के आर्थिक संबंध गल्फ और पश्चिम एशिया से काफी गहरे हैं। इस इलाके के कई देश भारत के बड़े कारोबारी पार्टनर हैं। 2023–2024 में भारत के कुल विदेशी व्यापार में इस क्षेत्र के देशों का योगदान 18.17 प्रतिशत था। यूएई भारत का तीसरा तथा सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। खाड़ी देशों में काम करने वाले

भारतीय कमाकर जो पैसा भेजते हैं यानी भारत की कुल रेमिटेंस में गल्फ देशों में काम करने वाले भारतीयों का योगदान करीब 40 प्रतिशत है। ईरान– इज़राइल जंग से भारत के हितों पर सीधा असर पड़ने की आशंका भी रहती है। क्योंकि ट्रम्प पर ईरान के प्रतिबंध से पहले ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश था। इसके अलावा पश्चिम एशिया से तेल स्ट्रेट ऑफ होरमुज के ज़रिए भारत आता है और इस पर नियंत्रण ईरान का भी है। भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षित रूप से तभी चल सकेगा जब ट्रेड रूट सुरक्षित रहेंगे। भारत अपना आयात यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, भू–मध्यसागर और उत्तरी अमेरिका के बाज़ार में ओमान की खाडी, फारस की खाड़ी और लाल सागर के ज़रिए भी करता है। अगर ईरान किसी भी समय एक लम्बे चलने वाले युद्ध की चपेट में आता है तो ये व्यापार मार्ग भी प्रभावित हो सकता हैं। यूएई और मिश्र में भारत के राजदूत रहे नवदीप सूरी के अनुसार– ''खाड़ी के दशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं और 50 प्रतिशत से ज्यादा ऊर्ज़ा आयात इसी क्षेत्र से होता है, ऐसे में इस इलाके में अशांति होगी तो भारत के लिए किसी भी लिहाज़ से कभी भी ठीक नहीं होगा।'' भारत का पड़ोसी चीन वैसे तो स्वयं को एक तटस्थ और ज़िम्मेदार शक्ति के रूप में दिखाता है, लेकिन उसकी वफादारी किसी भी अन्य देश की तरह ही सीमित है। ईरान और इज़राइल युद्ध में चीन ने ईरान को अपना खुलकर समर्थन दिया है। वहीं दूसरी ओर ईरान और रूस रणनीतिक सहयोगी हैं, और काकेशस में आर्मेनिया के साथ मिलकर एक धुरी का निर्माण करते हैं। ईरान और रूस, सीरिया और इराक़ में संघर्षों में सैन्य सहयोगी भी हैं और अफ़ग़ानिस्तान तथा सोवियत संघ के बाद के मध्य एशिया में साझेदार भी है साथ ही रूसी संघ ईरान को हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। इस सब के बीच भारत को अपने संबंधों को ईरान– इज़राइल परिप्रेक्ष्य में तटस्थता के साथ संतुलनकारी कूटनीतिक निर्णयों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक होगा।

➢ निष्कर्ष :

ईरान– इज़राइल संघर्ष, जो ऐतिहासिक, वैचारिक और भू–राजनीतिक तनावों में निहित हैं, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए ख़तरा उत्पन्न करता है। भारत के लिए यह ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर जोखिम उत्पन्न करता है। शत्रुता को कम करने और पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक समाधान, परमाणु अप्रसार और क्षेत्रीय सहयोग अनिवार्य है। ईरान– इज़राइल संकट में भारत की भागीदारी प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों के बीच एक सूक्ष्म संतुलनकारी कार्य को दर्शाती हैं। भारत आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में अमेरिका के नेतृत्व वाली पहलों के साथ जुड़कर, चीन के क्षेत्रीय प्रभाव के विकल्प प्रस्तुत करके, और रूस तथा ईरान के साथ स्वतंत्र सुरक्षा संबंध बनाए रखकर अपनी संप्रभुता और अवसर दोनों की रक्षा करता हैं।

➢ संदर्भ :

1. बीबीसी हिन्दी आर्टिकल, जून 2025।
2. भारत–ईरान संबंध, संस्कृति आईएएस पत्रिका, 2025।
3. राज अभिषेक, इज़राइल–ईरान कॉन्फिलिक्ट : ए स्ट्रैटेजिक फलशपॉईंट थ्रो इण्डियाज़ लैंस, शोध आलेख, 29 जून 2025।
4. फोरम आईएएस पत्रिका, 30 जून 2025।
5. भाटिया बृज राकेश, ईटीवी भारत समाचार लेख, 19 जून 2025।
6. विज़न आईएएस पत्रिका, जून 2025।
7. दैनिक भास्कर समाचार पत्र, जून 2025।
8. भारतीय विदेश मंत्रालय, प्रेस विज्ञप्ति।
9. पंत पुष्पेश, पाण्डे डॉ. जितेन्द्र कुमार, ''21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध'', मैक्ग्रा हिल एज्युकेशन (इंडिया) प्रा. लि., चैन्नई : 2025।
10. https://www.specialeurasia.com/2025/06/14/central-asia-israel-iran-war/
11. https://www.livemint.com/news/world/iranisrael-war-escalation-to-impact-india-s-trade-with-west-asia-say-experts-11750584950387.html
12. https://timesca.com/the-ripple-effects-of-the-israel-iran-conflict-on-central-asia/
13. https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/iran-israel-war-threat-looms-over-indias-3-6-lakh-crore-trade-crude-oil-prices-likely-to-rise/articleshow/122005434.cms
14. https://www.etvbharat.com/hi/!opinion/israel-iran-war-a-middle-eastern-conflict-with-asian-consequences-hin25061901053
15. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/iran-israel-conflict-2025